मैसर्स सी लार्क फिशरीज

विरूद्ध

संयुक्त भारत बीमा कंपनी और अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 803)

30 जनवरी, 2008

{एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.}

अनुबंध: बीमा का अनुबंध — समुद्री बीमा — समुद्री जहाज का बीमा — भौतिक तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण आयोजित: अस्वीकृत बीमा पॉलिसी— , 1963 — एसएस.19,20,21 और 41 (3) — तमिलनाडु माइनर पोर्ट्स हार्बर क्राफ्ट नियम, 1953 आर.आर. 31 और 32.

अपीलकर्ता के पास एक समुद्री जहाज था। उसने बैंक से ऋण लिया। बैंक ऋण की मंजूरी के समय, बैंक उक्त जहाज के संबंध में बीमा पॉलिसी प्राप्त की डीएम को हस्ताक्षरित प्रस्ताव फॉर्म सौंपकर उत्तरदाता नंबर 1-बीमा कंपनी का एजेंट, जिसने भरा था। विवरण स्वयं जारी किया और नीति जारी की। समुद्री जहाज डूब गया। उस ओर से दावा किया गया, एक सिविल सूट, उत्तरदाता नंबर 1 द्वारा निरस्त किए जाने के बाद, अपीलकर्ता

और बैंक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था। अपने लिखित बयान में उत्तरदाता नंबर 1 ने कहा कि जहाज समुद्र में चलने योग्य नहीं था। इस मुकदमे का फैसला उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए किया था कि, डी. डब्ल्यू. 1 ने कई सामग्री छोड़ दी है। कालम खाली होने के कारण बैंक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। अपील होने पर पर, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दें। इस न्यायालय में अपील करने पर, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ क्या तथ्यों का भौतिक दमन हुआ था? प्रतिवादी क्रमांक 1 बीमा कंपनी जिसमें बीमा पॉलिसी को अस्वीकार्य बना दिया। न्यायालय ने अपील खारिज की और अभिनिर्धारित किया-

1.1. समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 की धारा 19 में कहा गया है कि बीमा उचित है। एस 20 बीमाक्रत द्वारा किए गए प्रकटीकरण को निर्धारित करता है। प्रश्न यह है कि क्या एक विशेष परिस्थिति जिसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है सारभूत या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। किन तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता है और किन तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि एस 20 की उप-धाराओं 2 और 3 में निर्धारित किया गया है। अधिनियम की धारा 21 में बीमा को प्रभावित करने वाले एजेंट द्वारा प्रकटीकरण का प्रावधान है। कोई

भी बैक जिसमें एक एजेन्ट के रूप में कार्य किया है उसको सभी सारभूत तथ्यों को प्रकट करने का उत्तरदायित्व था। [पैरा १५] [३५२-डी, ई]

1.2. बीमा के अनुबंध की शर्तें क़ानून के प्रावधानों द्वारा शासित, ऐसे भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने से नीति अस्वीकार करने योग्य हो जाएगी। डी डब्ल्यू 1 के अनुसार आवश्यक विवरण वादीगण द्वारा उसको उपलब्ध नहीं कराया गया था। डी डब्ल्यू 1 किस तरह से बैंक के अधिकारियों के मौखिक प्रतिनिधित्व पर कैसे कार्य कर सकता है? यह सामान्य आदमी की समक्ष से परे है। इस प्रकार, उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। [पैरा १६] [३५२-एफ, जी; 354-डी, ई]

1.3. तमिलनाडु माइनर पोर्ट्स हार्बर के क्राफ्ट रूल्स, 1953 के नियम 31 में यह आज्ञात्मक प्रावधान है कि प्रत्येक यंत्रवत जहाज जो कि उपयोग में लाया जाता है, पर एक मास्टर या सेरांग और एक इंजीनियर या इंजन चालक की नियुक्ति अनिवार्य है। चालक के पास मत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। नियम 32 में मास्टर और सेरांग की योग्यता के बारे में प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त् किया जाता है विहित किया गया है। यहा तक भी बीमा के प्रस्ताव में तथाकथित विवरण नहीं था तथा कोई साक्ष्य भी रिकार्ड पर पेश नहीं किया गया। [पैरा 10] [351-बी, सी, डी]

1.4. जहां तथ्यों को छुपाया गया है, वहां पर बीमा कंपनी के एक अधिकारी द्वारा पॉलिसी की स्वीकृति भी कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, वैधानिक प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि वादीगण द्वारा सारभूत तथ्यों को छिपाया गया है। [पैरा 17] [354-ई, एफ]

2. एक समुद्री बीमा पॉलिसी के लिए समुद्र में सुरक्षा हेतु अन्तर्निहित वारन्टी होना आवश्यक है जो कि धारा 41 की उपधारा 3 में स्पष्ट है जिसमें की बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लेख है। हो सकता है कि दावे के निरस्त करने वाले नोटिस में सारभूत तथ्यों की कथित गलत बयानी के संबंध में कोई विवरण नहीं था, लेकिन यह निर्णायक नहीं था। यह वादीगण पर था कि केवल अभिकथन ही न करें बल्कि यह साबित भी करें कि प्रश्नगत जहाज पानी में चलने योग्य था। इस तरह के अभिकथन की जहाज पानी में चलने योग्य था वादपत्र में नही किए गए थे। [पैरा 13, 14, 17] [351-ए, सी; 354-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नम्बर 803/2008

मद्रास उच्च न्यायालय के ओएसए नम्बर 48/1998 तथा क्रास आब्जेक्शन नम्बर 37/2005 के अन्तिम निर्णय लेने तथा आदेश दिनांक 07/10/2005 से उत्पन्न।

विपिन गोगिया, जसप्रीत गोगिया और के.के. गोगिया अपीलकर्ता की ओर से।

एस.एम. सूरी तथा मंजीत चावला उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस श्री एस बी सिन्हा द्वारा दिया गया।

1. याचिका स्वीकृत।

2. अपीलकर्ता सी लार्क नामक समुद्री जहाज का मालिक था। जहाज मछली पकड़ने के उद्देश्य से लगाया गया था। अपीलकर्ता ने केनरा बैंक से ऋण प्राप्त किया। ऋण की मंजूरी के समय, बैंक ने प्रतिवादी संख्या से एक बीमा पॉलिसी प्राप्त की। उक्त जहाज के संबंध में 1. इसका बीमा 12.04.1979 को 1 कई मुद्दे तय किये गये. मुद्दे संख्या 2 और 4 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं वे इस प्रकार हैं: 2.04.1979 से 12.04.1980 तक की अवधि को कवर करने के लिए किया गया था। तत्पश्चात इसे 12.04.1980 और 11.04.1981 की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया। जहाज 21.07.1980 को डूब गया। इस संबंध में एक दावा किया गया था, जिसे प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, 1983 के सूट नंबर 333 के रूप में चिह्नित एक सिविल मुकदमा अपीलकर्ता और बैंक द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। प्रतिवादी नं.1

ने अपने जबावदावा में अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि जहाज समुद्र में चलने लायक नहीं था।

कई विवाद्यक तय किये गये विवाद्यक संख्या 2 और 4 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं वे इस प्रकार हैं:

2. आया प्रतिवादी क्लेम के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

3. आया प्रतिवादी पॉलिसी के तहत दायित्व को अस्वीकार करने में सही है?

4. उक्त दावा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डिक्री अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर किया गया था कि हेमचन्द्र बाबू जो बीमाकर्ता का एजेंट था और जिसने फार्म भरा था, उसने उसमें रिक्त स्थान दिया था। जिसके लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील की। हालांकि उक्त फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अनुमति दे दी है। अपीलकर्ता हमारे समक्ष है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन गोगिया ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह इस प्रश्न पर विचार करने में विफल रही है कि क्या जहाज के मास्टर के

पास अपेक्षित योग्यता थी या नहीं यह जबाव दावा में नहीं बताया गया था, वादी-अपीलकर्ता के पास इसे पूरा करने का कोई अवसर नहीं था।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम एस सूरी ने निर्णय का समर्थन किया।

7. वाद में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया था या गलत तरीकों से प्रस्तुत किया गया था तथा सुसंगत विवरण बीमाकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया था ? स्वीकृत रूप से मास्टर और क्रू के विवरण से संबंधित कॉलम के विपरीत, निम्नलिखित को इंगित करना आवश्यक था।

मास्टर और क्रू के विवरण

1. (ए) क्या जहाज का एक योग्यता प्राप्त मास्टर के अधीन है? हां
2. (बी) उसकी योग्यता बताएं? .....
3. (सी) वह आपके अधीन में कितने समय से नियोजित है? .....
4. (d) क्या वह जहाज विदेश में रहेगा? .....
5. यदि किसी योग्य का प्रभारी नहीं है तो जहाज के प्रभारी व्यक्ति का संक्षिप्त विवरण बताए .....

8. वाहन का बीमा करने के लिए एक आवेदन बैंक द्वारा दायर किया गया था. इसने बीमाकर्ता के एजेंट को एक हेमचंद्र बाबू होने के लिए कुछ

जानकारी दी. उन्होंने खुद को डी डब्ल्यु-1 के रूप में जांचा। यह बैंक द्वारा अपने प्रतिनिधित्व में अध्यक्ष और उत्तरदाता के प्रबंध निदेशक के समक्ष स्वीकार किया गया है. 1 — कंपनी है कि कुछ चूक हुई थी; स्पष्टीकरण, हालांकि, इसके संबंध में निम्नलिखित शर्तों में प्रस्तुत करने की मांग की गई थी:

> "स्वाभाविक रूप से यह समुद्री नीति संयुक्त भारत बीमा को भी पारित की गई थी. हस्ताक्षरित प्रस्ताव पत्र एजेंट को सौंप दिया गया था और सभी अवसरों में, उसने स्वयं विवरणों को भर दिया और नीति जारी की. वह अपने व्यवसाय के लिए हमारी शाखा का लगभग दैनिक आगंतुक है. इस मामले में, केवल यह कि पक्षकार मद्रास से दूर थी, हमने प्रीमियम स्वीकार करने और कवर नोट जारी करने का सुझाव दिया और कहा कि पक्षकार वापस आते ही हम प्रस्ताव फॉर्म दे देंगे. हालांकि, जैसा कि एजेंट द्वारा सुझाया गया है, हमने उसे 12.4.79 पर पॉलिसी जारी करने में सक्षम बनाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, ताकि बीमा कवर में कोई विराम न हो. उससे कुछ भी नहीं छिपाया गया।."

9. बैंक द्वारा बीमाकर्ता को जो भी जानकारी दी जा सकती थी, वह केवल अपीलकर्ता से प्राप्त जानकारी के आधार पर थी। बैंक के पास इस संबंध में कोई स्वतंत्र जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी। हमने पाया कि कई कॉलम जो बीमा के अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण थे, खाली छोड़ दिए गए थे।

10. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने तमिलनाडु माइनर पोर्ट्स हार्बर क्राफ्ट नियम, 1953 के नियम 31 पर ध्यान दिया है, जो उपयोग किए जाने पर प्रत्येक यांत्रिक चालित जहाज में एक मास्टर या सेरांग और एक इंजीनियर या इंजन ड्राइवर की नियुक्ति को अनिवार्य करता है। चालक के पास मत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उक्त नियमों में नियम 32 मास्टर या सेरांग के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि निर्धारित करता है। बीमा के प्रस्ताव में न केवल उक्त विवरण शामिल नहीं था बल्कि इस संबंध में कोई साक्ष्य भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था।

11. विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलकर्ता को सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी कोई दलील वादपत्र में नहीं उठाई गई थी।

12. श्री गोगिया ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि जहाज समुद्र में चलने योग्य था। निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.04.1980 है। 25.11.1979 को शाम 6 बजे एक सर्वेक्षक द्वारा (हमें नहीं पता कि किसके कहने पर) एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, ऐसा सर्वेक्षण किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था, यह ज्ञात नहीं है। सर्वे कराने के चार माह से अधिक समय बाद रिपोर्ट क्यों सौंपी गयी, यह भी समझ से परे है.

13. समुद्री बीमा पॉलिसी के लिए समुद्री योग्यता की एक निहित वारंटी की आवश्यकता होती है जैसा कि समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 41 की उप-धारा (3) से स्पष्ट है जो बीमा के अनुबंध की शर्तों को नियंत्रित करता है। यह सच हो सकता है कि दावे को खारिज करने वाले दिनांक 9.11.1981 के नोटिस में भौतिक तथ्यों की कथित गलत बयानी के संबंध में कोई विवरण नहीं था, लेकिन यह निर्णायक नहीं था। वादी को न केवल तर्क देना था बल्कि यह साबित करना था कि प्रश्नगत जहाज समुद्र में चलने योग्य था। वादपत्र में ऐसा कथन नहीं था।

14. वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 7.1.1983 को एक नोटिस दिया था जिसमें प्रतिवादी से भुगतान करने का आह्वान किया

गया था। यद्यपि उक्त नोटिस प्रतिवादी द्वारा प्राप्त और स्वीकार किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने दिनांक 15.3.83 को एक जबाव भेजा था जिसमें गलत और अस्थिर तर्क उठाए गए थे।

14. वादपत्र में यह भी अभिकथन नहीं उठाये गये है कि वाहन समुद्र में चलने योग्य था। अपने जबावदावा में, प्रतिवादी नंबर 1 ने कहा: प्रतिवादी का तर्क है कि हस्तलिखित उत्तर भी हेमचंद्र बाबू या प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरे गए थे।

15. अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि बीमा उबरिमे फिदेई है। धारा 20 बीमित व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण का प्रावधान करती है। यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष परिस्थिति जिसका खुलासा नहीं किया गया है, भौतिक है या नहीं, मूलतः तथ्य का प्रश्न है। किन तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता है और किन तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, यह क्रमशः धारा 20की उपधारा (2) और (3) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। बीमा को प्रभावित करने वाले एजेंट द्वारा प्रकटीकरण का प्रावधान करती है।इस प्रकार, एक एजेंट के रूप में कार्य करने के कारण, बैंक की सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने की जिम्मेदारी थी।बीमा पॉलिसी को एक्सटेंशन के रूप में चिह्नित किया गया था। डी-18 इसका

उल्लेख वाद-पत्र में भी किया गया था।हमने इसके पहले इसके भौतिक भाग पर ध्यान दिया है।

16. बीमा अनुबंध की शर्तें, इस प्रकार, एक क़ानून के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं; ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करने से नीति अस्वीकार्य हो जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, हम डीडब्ल्यु-1 के निक्षेपों को देख सकते हैं, जो प्रश्न और उत्तर के रूप में हैं, जो निम्नानुसार हैं:

प्र. मास्टर और क्रू का विवरण देखें। यहा पर शीर्षक है जनरल पहले शीर्षक के तहत, प्रश्न का जबाव योग्य मास्टर के जहाज प्रभारी का उत्तर क्या है?
उत्तर: हाँ।

प्र. सामान्य शीर्षक के अंतर्गत तीन प्रश्न हैं। क्या प्रश्नों के संबंध में आपको कोई जानकारी दी गई?

उत्तर: उन्होंने तीन प्रश्नों के लिए कोई जानकारी नहीं दी थी।

*** *** ***

प्र. आपने कहा कि प्रस्ताव प्रपत्र आपके कार्यालय में टाइप किया गया था। क्या आपने यह सूचना अपने कार्यालय में दी?
उत्तर: मैंने विवरण एक कागज में नोट कर लिया और और उन्हें कार्यालय में बताया।

प्र. आपने बैंक अधिकारियों से पूछा होगा कि होगी कि कौनसी सूचना की आवश्यकता है?

उत्तर: मेरे पास उनके लिए प्रस्ताव है और उन्होंने जो भी सूचनादी, उसे मैंने एक पेपर पर नोट कर लिया था।

प्र. क्या आपके पास कोई कागज है?

उत्तर: नहीं।

प्र. आपने पेपर में दी गई जानकारी को किस प्रकार या सामान्य रूप से नोट किया?

उत्तर. कॉलम-वार।

प्र. आप पाते हैं कि प्रस्ताव के शीर्ष पर 10.05 मीटर का उल्लेख किया गया है। क्या यह सही है?

उत्तर: हाँ।

प्र. स्याही से यह लेख कब बनाया गया?
उत्तर: इसे टाइप करने के बाद, मैं इसे वापस बैंक ले गया और उनसे सूचनओं की जांच करने के लिए कहा कि क्या वे सही हैं।

*** *** ***

प्र. आपको बोर्ड के स्वामी का नाम बैंक से मौखिक या लिखित रूप से मिल गया था

उत्तर: मौखिक रूप से अधिवक्ता द्वारा:

प्र. क्या आपको मौखिक प्रतिनिधित्व स्वीकार करने की आदत है?
उत्तर: हां।

प्र. यदि मेरा विद्वान मित्र कहता है कि बीमा केवल प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था तो क्या यह गलत है।
उत्तर: नहीं, यह ग़लत नहीं है।

प्र. क्या आप स्वीकार करने वाले प्राधिकारी हैं?
उत्तर: मेरा शाखा प्रबंधक स्वीकारकर्ता प्राधिकारी है।

प्र. शाखा प्रबंधक के पास प्रस्ताव लेकर जाने के बाद आपने क्या किया?
उत्तर: मैंने शाखा प्रबंधक को प्रस्ताव दिखाया और उन्होंने मुझसे पॉलिसी जारी करने के लिए कहा। इस प्रकार, डीडब्ल्यू-1 के अनुसार भी, वादी द्वारा उसे आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। डीडब्ल्यू-1 बैंक के अधिकारियों के कथित मौखिक प्रतिनिधित्व पर कैसे कार्रवाई कर सकता है, यह सामान्य प्रज्ञावन व्यक्ति की समक्ष से परे है। अत: उसके साक्ष्य पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता।

17. जहां तथ्य को छुपाया गया हो, वहां बीमा कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा पॉलिसी स्वीकार करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, हमारी राय में, वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सही माना है कि वादी ने महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया। इसके अलावा, वैधानिक नियमों के मद्देनजर, अदालत के पास यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा कि जहाज समुद्र में चलने योग्य नहीं था।

18. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जाती है. हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा हुड्डा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।